भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 333

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है।

***

जल की कमी

333. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पानी की कमी आज देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नदियों, झीलों, भूजल और भूजल के अन्य स्रोतों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में सहभागी भूजल प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या पहल की गई है; और

(घ) देश में उपलब्ध जल संसाधनों के संरक्षण, सुरक्षा और संवर्धन के तरीके खोजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क) और (ख): किसी भी क्षेत्र या देश की औसत वार्षिक जल उपलब्धता काफी हद तक जल-मौसम विज्ञान और भूवैज्ञानिक कारकों पर निर्भर करती है। हालाँकि, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता किसी देश की जनसंख्या पर निर्भर है। जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता घट रही है। 1700 क्यूबिक मीटर से कम वार्षिक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को जल संकट की स्थिति माना जाता है। "अंतरिक्ष इनपुट का उपयोग करके भारत में जल की उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन" (सीडब्ल्यूसी, 2019) के अध्ययन के आधार पर, वर्ष 2031 के लिए प्रति व्यक्ति जल की औसत वार्षिक उपलब्धता 1367 घन मीटर आंकी गई है।

गतिशील भूजल संसाधन आकलन 2022 के अनुसार, देश में कुल 7089 मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉक/तालुक/मंडल/वाटरशेड/फिरका) में से 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 1006 इकाइयों को 'अति-शोषित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है जहां वार्षिक भूजल निष्कर्षण वार्षिक

भूजल निष्कर्षण से अधिक है, 260 इकाइयों को 'सेमी-क्रिटिकल', 4780 इकाइयों को 'सुरक्षित' और 158 इकाइयों को 'लवणीय' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) और (घ): जल राज्य का विषय है, जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए कदम मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

अटल भूजल योजना, 6000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारत सरकार की विश्व बैंक सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे चिन्हित जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी और मांग पक्ष के हस्तक्षेप पर ध्यान देने के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना सात राज्यों में शुरू की जा रही है, अर्थात हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले राज्यों में समुदायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जैसे भूजल डेटा की निगरानी और प्रसार, जल बजट, ग्राम-पंचायत वार जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी और सतत भूजल प्रबंधन से संबंधित चल रही योजनाओं और आईईसी गतिविधियों के अभिसरण के माध्यम से उनका कार्यान्वयन शामिल है।

जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) लागू कर रही है। पीएमकेएसवाई-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत, राज्यों के परामर्श से 2016-17 के दौरान चल रही 99 बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई थी, जिनमें से 50 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के एआईबीपी कार्यों को पूरा करने की सूचना दी गई है। 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के विस्तार को भारत सरकार द्वारा 93,068.56 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है।

कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम को 2015-16 से पीएमकेएसवाई - हर खेत को पानी के तहत लाया गया है। सीएडी कार्यों को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग बढ़ाना और भागीदारी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) के माध्यम से सतत आधार पर कृषि उत्पादन में सुधार करना है।

भारत सरकार, राज्य के साथ साझेदारी में, 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के जल की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) को लागू कर रही है। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए संचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को 'राज्य कार्य योजना' तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यव्यापी कायाकल्प और ग्रामीण जल निकायों/पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं की सफाई, ग्रे जल उपचार और पुन: उपयोग के लिए कार्यनीतियां विकसित करना शामिल है। इस प्रकार, जल निकायों का संरक्षण और संरक्षण पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने में सहायक होगा।

भारत सरकार ने 1 अक्टूबर, 2021 को अमृत 2.0 लॉन्च किया है, जिसमें देश के सभी वैधानिक शहरों को शामिल किया गया है ताकि जल की आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित किया जा सके और शहरों को 'जल सुरक्षित' बनाया जा सके। यह जल निकायों के कायाकल्प, शहरी जलभृत प्रबंधन, पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग को बढ़ावा देने और मीठे जल के संसाधनों को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन की परिकल्पना करता है। शहरी जलभृत प्रणालियों में सकारात्मक भूजल संतुलन बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जलभृत प्रबंधन योजना भी तैयार की जाएगी।

सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्र में जल के कुशल उपयोग के प्रचार, विनियमन और नियंत्रण के लिए जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूयूई) की स्थापना की गई है। ब्यूरो देश में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, उद्योगों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता में सुधार को बढ़ावा देने के लिए एक सुविधा प्रदाता होगा।

जल की कमी वाले क्षेत्रों में किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रेरित करने के लिए "सही फसल" अभियान शुरू किया गया था, जो जल की अधिक खपत नहीं करती हैं, लेकिन जल का बहुत कुशलता से उपयोग करती हैं; और आर्थिक रूप से लाभकारी हैं; स्वस्थ और पौष्टिक हैं; क्षेत्र की कृषि-जलवायु-हाइड्रो विशेषताओं के अनुकूल हैं; और पर्यावरण के अनुकूल हैं। जल की कमी को नियंत्रित करने और वर्षा जल संचयन/संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम यूआरएल: http://jalshakti-dowr.gov.in/sites/default/files/Steps%20taken%20by%20the%20Central%20Govt%20for%20water_depletion_july2022.pdf पर उपलब्ध हैं।

*****